EIU की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट

प्रीलिम्स के लिये:

इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वित्तीय समावेशन रिपोर्ट

मेन्स के लिये:

वित्तीय समावेशन से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intelligence Unit- EIU)** ने **'ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019: द एनेबलिंग एन्वायरनमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूज़न रिपोर्ट' (Global Microscope 2019-The Enabling Environment On Financial Inclusion)** जारी की।

निष्कर्ष:

- उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्तीय समावेशन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।
- भारत वित्तीय समावेशन के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से 5वें स्थान पर है।
- इस सूची में शीर्ष पर कोलंबिया है, इसके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः पेरू, उरुग्वे और मेक्सिको हैं।
- 55 देशों की इस सूची में सबसे नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (Democratic Republic of Congo) है।
- ज्ञातव्य है कि इन सभी मानदंडों पर सिर्फ 4 देशों को पूरे अंक मिले, इनमे भारत, कोलंबिया, ज़मैका और उरुग्वे शामिल हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

- इस रिपोर्ट में 55 देशों और 5 क्षेत्रकों को शामिल किया गया है:

1. शासन और नीति समर्थन
2. उत्पाद और निर्गम
3. स्थिरता और अखंडता
4. उपभोक्ता संरक्षण
5. आधारभूत ढाँचा

- उपर्युक्त रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्नलिखित 4 मानदंडों को शामिल किया गया:
    - गैर-बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति।
    - वित्तीय सेवा एजेंटों की मौजूदगी।
    - आनुपातिक आधार पर ग्राहकों की जाँच-परख।
    - प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण।
- रिपोर्ट के इस संस्करण में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 11 लिंग-आधारित संकेतक भी जोड़े गए।

Summary of India's performance

	Category	Score	Rank	Average score
	Overall score	71	=5	52
1	Government and policy support	76	=8	54
2	Stability and integrity	76	12	65
3	Products and outlets	92	3	57
4	Consumer protection	81	9	60
5	Infrastructure	60	31	59

India: strengths			India: areas for improvement		
Indicator		Rank	Indicator		Rank
2.3	Customer due diligence	=1	2.4	Supervisory capacity	=29
3.2	Credit portfolios for middle- and low-income customers	=1	5.3	Connectivity	=45
3.3	Emerging services	=1	1.1	Broad strategies for financial inclusion	=19

//

भारत के संदर्भ में:

- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के डिज़िटिलीकरण के लिये मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
- अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox- RS) के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वित्त, औद्योगिकी और स्टार्टअप्स (Startups) को नई तकनीक एवं सेवाओं के परीक्षण के लिये आधार उपलब्ध कराएगा।

रेगुलेटरी सैंडबॉक्स:

- सैंडबॉक्स एक बुनियादी ढाँचा है जो बैंक द्वारा फिनटेक कंपनी को उपलब्ध कराया जाता है ताकि उत्पादों या सेवाओं के तैयार होने के बाद एवं बाज़ार में आने से पहले उनका परीक्षण किया जा सके।

फिनटेक क्या है?

- फिनटेक (FinTech) Financial Technology का संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों में प्रौद्योगिकी के उपयोग को फिनटेक कहा जा सकता है।
- दूसरे शब्दों में यह पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का कार्यान्वयन है।
- पहले बैंक में किसी विवरण को रजिस्टर पर लिखा जाता था जिसमें काफी समय भी लगता था। वर्तमान में अब बैंकिंग प्रणाली में प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कोर बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में आ गया है और इससे बैंकिंग प्रणाली आसान हो गई है। इस प्रकार की वित्तीय प्रौद्योगिकी को फिनटेक कहा जाता है।
- बैंकों द्वारा फिनटेक के माध्यम से मोबाइल वॉलेट सर्विस तथा UPI और भीम एप लॉन्च करके बैंकिंग प्रणाली को आसान बनाया जा रहा है।
- फिनटेक बैंकों के लिये भुगतान, नकद हस्तांतरण जैसी सेवाओं में काफी मददगार साबित हो रहा है, साथ ही यह देश के दूरदराज़ के इलाकों तक बैंकिंग सेवाएँ भी उपलब्ध करा रहा है।

स्रोत-द हिन्दू बिज़िनेस लाइन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/enabling-environment-on-financial-inclusion